पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक
समय माया

www.samaymaya.com

पंजीयन क्रमांक RNINDPM\HIN\20345/12/1/2006/TC

प्रधान संपादक-अजमेरा एस.पी.कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

cell : 9300755803-9425125569
Phone Fax : 91-731-2530859
Websites : www.samaymaya.com
www.geocities.com/corruption2india/eduIndore.html
www.geocities.com/corruption2india/corruptindia.html
www.geocities.com/corruption2india/corruptMP.html
E-mail : mwc@indiatimes.com
: linkdage@hotmail.com,
: linkadage@indiatimes.com
(c) all copyrights reserved with chief editor,do not publish any matter without prior permission.

वर्ष 1 अंक 45 इंदौर, सोमवार 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2008 तक पृष्ठ 8 मूल्य रु. 2/-

2 ✦मुम्बई ताज, ओबेराय, मेरियट होटल कांड

3 ✦असली आतंकियों को बचाना, संतों को प्रताड़ना

4 5 ✦न श्रमिकों की सुरक्षा, न वेतन पूरा

6 ✦समय माया के दो पत्रकार शाह के इशारे पर गिरफ्तार

7 ✦जालसाजी पूर्ण रिकार्ड नहीं दी छायाप्रतियां

आखिर समय माया का सच-5 वर्ष बाद माना

इराक पर आक्रमण–मेरी गलती बुश

50 लाख से ज्यादा इराकियों की मौत

1 करोड़ से ज्यादा घायलों के बाद स्वीकारा

अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने अपनी बिदाई बेला में स्वीकारा कि ईराक युद्ध उनके राजनैतिक जीवन की बड़ी भूल थी। बुश का मानना है कि राजनीति के लिए ईमान बेचने वाले के रूप में उन्हें कभी याद न किया जाए, अंतिम समय में सबको याद आती हैं भूलें,-बुश।

समय माया ने यह बात सन 2002 से लगातार लिखी और विरोध प्रकट किया जाता रहा कि वहां हथियारों के आधार पर आक्रमण कर तेल, हथियाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। रासायनिक और परमाणु हथियारों के जखीरे की बात करना केवल बकवासहै। सीधा ईराक पर युद्ध थोंप उस पर कब्जा कर अमेरिकी और ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों के लाभ की राजनीति है।

बेशक हमारी सच्चाई जो हम समय माया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करते हैं। सामने आती है दुनिया को स्वीकारना होता है जो हमने पृथ्वीवासियों के भविष्य को ध्यान में रखकर, वास्तविक कल्याण और विकास के लिए लिखा जाता है। अंत में स्वीकारना वही होता है।

ईराक संबंध में जब अमेपिकी राष्ट्रपति बुश ने स्वीकारा ही

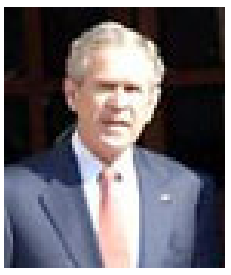

वक्त है उसे खाली कर दे नाटो सेनाएं

है कि वो भयानक भूल थी, अभी भी वक्त है जाते-जाते बुश नाटे सेनाओं को वहां से वापस बुलवा कर ईराक में लोकतांत्रिक सत्ता की स्थापना में सहयोग कर ईराक को पुनर्निर्माण का शीघ्र अवसर प्रदान करे, ताकि बुश अपने माथे का कलंक धो सके।

ईराक को पूर्णतः मुक्त कर दे उसके तेल और प्राकृतिक गैस को अपनी तरह से उपयोग, बेचने और निर्यात करने का अवसर प्रदान करे, ताकि अमेरिका का 270 अमेरिकी मिलियन डॉलर जो नाटो और अमेरिकी सैनिकों पर खर्च हो रहा है उसे मंदी से त्रस्त अर्थव्यवस्था रको उबारने में खर्च करें।

अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी

इराक में 50 लाख से ज्यादा लोगों को अमेरिका द्वारा 20/3/2003 से लादे गए युद्ध में मौत हो चुकी है। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के धंधे रोजगार उजाड़ हो चुके हैं। 2 करोड़ से ज्यादा 18 वर्ष से कम आयुक के बच्चे, अवयस्क अनाथ हो चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग नाटे और अमेरिकी सेनाओं के अत्याचारों के चलते विस्तापितों की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। इससे बड़ा आतंकवादी कौन होगा? **शेष पेज 2 पर**

मुम्बई होटलों में विस्फोट

क्या संतों की आह! ले डूबी एटीएस को

मुम्बई। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हेमंत करकरे ने कांग्रेस के इशारे पर जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा, स्वामी अमृतानंद, दयानंद पांड्ये, कर्नल पुरोहित की जिस तरह से झूठे केसों में फंसाकर प्रताड़ित किया गया उसका परिणाम देश और दुनिया के सामने है। कि किस तरह एटीएस मुख्य हेमंत करकरे एक झटके में ही साफ हो गए।

बेशक इन सबको कांग्रेस समर्थित आतंकवादियों ने एक झटके में इसलिए कुत्ते-बिल्लियों की तरहसाफ कर दिया या करवा दिया गया कि कल जब मुकदमें न्यायालय में सुने जाएंगे तो ये सब टिक नहीं पाएंगे और सच्चाइयां सामने आएंगी तब हेमंक करकरे ने अगर सच खोल दिया तो कांग्रेस की न केवल देश में वरन दुनिया में भी सच्चाई मालूम पड़ेगी। दूसरा कर्नल पुरोहित भारतीय थल सेना के हैं। सेना जांच ब्यूरो भी इसकी सच्चाई की जांच कर हीरहा होगा, क्योंकि यह पूरे देश की सेना का देश की जनता व दुनिया की जनता के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सच्चाई प्रकट होने पर वो भी हेमंत करकरे की किरकिरी करते ही, इससे पहले उसको निपटाया जाना जरूरी था। यह सबसे बचने के लिए हेमंत करकरे को कांग्रेस के राज दबाए रखने के लिए हटाना जरूरी था।

जब साध्वी प्रज्ञा की पेशी हुई तो उसने जब सच बोला कि सारे फोन एटीएस ने ही करवाए थे तो कांग्रेस को छह राज्यों के चुनावों में जमीन खिसकती नजर आने लगी।

साध्वी प्रज्ञा को साथ एटीएस सारे दुष्कर्म किए हैं, परंतु वह बदनामी के डर से स्वयं सारे दुष्कर्मों के बारे में नहीं बता रही है। उसको एटीएस ने प्रताड़ित करने अपनी बात मनवाने के लिए सामूहिक दुष्कर्म किए, जितने संतों को पकड़ा उन्हें भी हरामखोरों ने मार-मार कर विक्षिप्त ही बना दिया। इसत रह इस कांग्रेसी श्वानों ने हिन्दुओं में पूरे देश में जो दहशत फैलाने मुसलमानों के वोट के लिए सिर बैठाकर नचाने का जो संदेश दिया। इसके कांग्रेस के बारे में समय मायी का यह सच कि अंग्रेजों की बनाई इस पार्टी को जाते समय देश पर राज करने का फूट डालो राज करो, हमने किया है तुम भी करो कि मंत्र सिद्धि से कांग्रेस राज करना चाहती है। ऐसे ही 50 वर्षों से उसने राज किया है। आतंकवाद फैलाया है, देश की जनता को मरवाया है। कभी हिन्दू-मुस्लिम दंगे करवाकर, कभी आतंकवाद का भय दिखाकर, कभी हिन्दुओं को आतंकित करने के लिए साधु संतों को परेशान कर गिरफ्तार कर जेल पहुंचा कर वैसे जिस तरह से ये कांग्रेसी श्वान वर्तमान में हिन्दुओं के साधु संतों को परेशान कर रहे हैं, इससे मुस्लिम शासकों का इतिहास याद आता है। जब वो हिन्दु संतों को परेशान करते, कारागारों में डालकर उन्हें धर्म विमुख कर मार-मार मुसलमान बनाते थे। बस इस लोकतांत्रिक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में अब मार-मार ईसाई बनाने के लिए सोनिया **शेष पेज 2 पर**

गोरे अमेरिकीयों को काले ओबामा की जीत नहीं पच रही

जातीय संघर्ष में अमेरिका , भारतीयों को खतरा

अमेरिका में ओबामा की जीत के बाद से वहां शनैः शनैः जातीय संघर्ष की आग भड़क रही है, अमेरिका के इतिहास में पहली बार काले राष्ट्रपति को चुना,यह काले राष्ट्रपति ओबामा को चुना जाना अमेरिकी गोरों को हजम नहीं हो रहा है। यही कारण है कि अमेरिकी गोरों का काले लोगों से अब सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। उन्हें अब अपनी श्रेष्ठता, गोरे होने का अभिमान, खंड-खंड बिखरता दिख रहा है। इसलिए इन गोरों का समूह अब इन काले अफ्रीकीयों पर आक्रमण कर रहा है।

जहां तक अमेरिका का सवाल है, वैसे भी पूरा अमेरिका संकर प्रजाति के लोगों का देश है, जहां पूरी आबादी चूंकि संकर प्रजाति की है तो स्वाभाविक है कि क्रूरता, दंभ, चालाकी, मक्कारी, लालच इनमें मां-बाप के गुणओं से कुछ ज्यादा ही होती है। स्वाभाविक है कि गोरों` बदलाव की दृष्टि से तो बदलाव कर लिया है पर अब उन्हें मानसिक पीड़ा दे रहा है। गोरे अमेरिकीयों को लग रहा है कि अब काले अफ्रीकी ओबामा को आने वाले चार वर्ष झेलना पड़ेगा, इसलिए तो अब एक जुटहोकर अफ्रीकीयों के साथ एशियाई मूल के लोगों पर भी हमला बोल रहे हैं।

अमेरिकी प्रशासन रंग, जाति, धर्म को आधार पर दुनिया को भले ही निरपेक्षता का पाठ पढ़ाता हो, संयुक्त राष्ट्र संघ में निरपेक्षता की बातें सिद्धांतों को दोहराया जाता हो, इसके विपरीत स्वयं अमेरिका की संकर प्रजाति में भी यह कूट-कूट कर भरा है।एशियाई विशेषतौर पर दक्षिण एशियाई मूल के भारतीयों, चीनीयों, बांग्लादेशीयों, पाकिस्तानियों पर खुलकर

अमेरिका में भारतीय दूतावास, तत्काल सुरक्षा संबंधी कदम उठाएं

चौराहों, विशाल विक्रय भंडारों में खुलकर नस्लभेदी टिप्पणीयां की जाती है।

अब जबकि पूरे विश्व के बाजार मंदी की चपेट में हैं, हर कंपनी अपने अस्तित्व के बचाए रखने के लिए कर्मचारियों में धड़ल्ले से कटौतियां कर रही हैं। स्वाभाविक है ऐसे समय हर नियोक्ता मालिक प्रबंधक उन कर्मचारियों को सबसे पहले बाहर करेगा जो ज्यादा नकचढ़े, कानूनबाज, क्षेत्रीय, नेतागिरी करने वाले को बाहर करेगा। एशियाइयों में भारतीय इन सबके विपरीत विदेशों में काम करने वाले भारतीयों को ज्यादा समय तक तन्मयता से करते हैं वह भी बिना न-नुकुर और कानूनबाजी दिखाए बिना,

खाद्य सुरक्षा एवं स्तर अधि-2006

खाद्य सुरक्षा व बहुराष्ट्रीय कं. हित सुरक्षा अधिनियम 06 दस करोड़ बेरोजगार, 30 करोड़ को दो वक्त की रोटी नहीं मिलेगी

मुख्य तथ्य-

- रिलायंस, टाटा, पेप्सी, कोकोकोला, आईटीसी जैसी बहुराष्ट्रीय कं. के दबाव और उनकी इच्छानुसार बनाया गया।
- ये बहुराष्ट्रीय कं. अपने उत्पादों से 2, 5, 10 नहीं, बल्कि करोड़ों को भी मिलावटी, जहरीली खाद्य सामग्री बेंचे, उससे यदि 10-20 करोड़ भी मरे, या मरणासन्न भी हो जाएंगे तो भी दंड के रूप में करावास नहीं दिया जा सकता केवल अधिकतम रु. 5 लाख आर्थिक दंड किया जा सकता है।
- इस कानून के लागू होने से लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे **शेष पेज 2 पर**

साप्ताहिक
समय माया

संपादकीय

मुम्बई ताज, ओबेराय, मेरियट होटल कांड
कांग्रेसियों कब तक रक्तपान करोगे, इस देश का...

ये राष्ट्र गुलामों का राष्ट्र है, यहां पर निवास करने वालों को देशी कुछ भी अच्छे से अच्छा नहीं लगता, इसलिए इन्हें उनकी ही सत्ता सुहाती है, जो इनका रक्तपान करते रहें।

कांग्रेसियों को सत्ता सौंपते समय अंग्रेजों की बनाई इस पार्टी ने सत्ता सौंपते समय जो गुरु मंत्र दिया था, कि हमने इस देश पर हिन्दुओं-मुस्लिमों को लड़वा कर राज किया है, तुम्हें राज करना हो तो इन्हें लड़वा कर इनका रक्तपान करते हुए ही राज कर सकते हो, इसलिए जब छह राज्यों में मतदान होना था, इन्होंने जनता का ध्यान हटाने, दहशत बरपाने, मीडिया में छाने के लिए मुम्बई की होटलों में बम कांड करवा दिया जैसे-जैसे राज्यों का मतदान समाप्त होता गया, एक-एक करके होटलें मुक्त होती गईं।

होटल में आतंकवादियों ने रूस के यात्रियों को पासपोर्ट देखकर इसलिए नहीं छोड़ा कि वो रुसी थे, वरन् रुसियों को न छोड़ने का मतलब होता कि रूस अपने कमांडों भेजकर अपने नागरिकों को छुड़वाता ये अमेरिका और ब्रिटेन की दादागिरी पर सीधा आघात होता, दूसरा भारत सरकार में सत्ता के मजे ले रही रक्तपान कर रही कांग्रेस की भी पोल खोल देता। यही कारण था कि इस इतने बड़े कांड में सभी रूसी नागरिक को चुपचाप छोड़ दिया गया।

हिन्दु संतों, साध्वियों, सेना के कर्नल को जिस तरह एटीएस द्वारा परेशान किया गया, जब पूरे मीडिया में एटीएस की धज्जियां उड़ने लगी, उसका खलनायकी चेहरा सामने आने लगा, फिर कांग्रेस की सच्चाई, बदनीयती, हिन्दुओं को नीचा दिखाने, उन्हें मुसलमानों के प्रति और मुसलमानों को हिन्दुओं के प्रति भड़काने का षड्यंत्र नाकाम होते देख मुम्बई कांड करवा दिया गया, ताकि मतदाताओं को मोड़, वोट तोड़ा जा सके और एटीएस की खलनायकी छवि को सुधारा जा सके,ि जिन्होंने ये कांड किया व करवाया था। न्यायालय में पेश हो इसके पहले उन्हें निपटा दिया जाए वरना और धज्जियां उड़ेंली, इसलिए इस मुम्बई के होटल कांड से एक साथ तीनों निपटा दिए गए, और शहीद का दर्जा देकर उन्हें नायक बना दिया गया, हिन्दु संतों को बेवजह परेशन करना का मामला दबा दिया गया।

जब जनता आक्रोशित होने लगी तो गृहमंत्री का इस्तीफा लेकर उस भ्रष्ट कर सलाहकार वकील पी. चिदंबरम को सौंप दिया गया, जिसने पहले कमीशन खाकर महंगाई बांटी। आखिर ये जालसाजियों, सत्ता के खेल में कब तक जनता का तेल निकालकर भी उसका रक्तपान करते रहेंगे। पड़ोसियों के ऊपर लांछन लगाकर अपने पापों से जनता को बरगलाएंगे, सत्ता में बैठ जनता की लाशों की होली जलाएंगे। इन बेशर्म, निकम्मों, नीचों को कब तक फिर भी हम सिर पर बैठाएंगे। आतंक इन श्वानों का हथियार बन चुका है, जनता को डराने, कुकर्मों से ध्यान हटाने, सत्ता में बैठे मौज उड़ाने का इन्हें सत्ता से मतलब है ये क्या जनता , क्या प्रशासन, क्या सेना, क्या साधु-संत सब इनके लिए खिलौने हैं। जब तक चाहा दिल से खेला जब चाहा तब तोड़ दिया।

सत्ता पाने, बनेरहने के लिए इन हरामखोर कांग्रेसियों का कोई ईमान धरन तो दूर रक्तपात और रक्तपान करने से भी इन्हें परहेज तो दूर, दिल पर दिमाग पर भी नहीं लेते, सत्ता में बैठे बेरहम और निष्ठुर पहली आवश्यकता होती है बेचारे बहुत वर्ष सत्ता से दूर रहे हैं। अब सत्ता में आए हैं। सारे खेल देखना और दिखाना अपना वर्चस्व बताना, अपनी सत्ता का अहसास कराना जरूरी है। इन नीचों को।

हिन्दुओं का स्वार्थी निकम्मापन और भाग्यवादिता इनके लिए वरदान है। ये कुछ भी करेंगे उन्हें मालूम है ये ठीक कुछ भी नहीं करेंगे, न अच्छे के लिए, न बुरे के लिए, सत्ताधीशों को ऐसी ही नपुसंकता और नकारा कौम चाहिए। यही इनकी गुलामी का सबसे बड़ा कारण रही है और रहेगी, ऐसे ही कुचली जाएगी, मारी जाएगी। वो झूठे शब्दों का मायाजाल बिछा कर कभी आतंकवाद से कभी साम्प्रदायिक दंगे करवाकर अपनी रक्त पिपासा शांत करते रहेंगे।

कार्रवाई खत्म होटल के बाहर निकलते कमांडो।

संतों की..

पेज 1 से जारी

पोप के इशारे पर ईसाई बनाने के लिए किया जा रहा है।

इस कांग्रेसी सोनिया, मनमोहन ने जिस प्रकार से एटीएस से हिन्दुओं के संतों, साध्वीयों, सेना अधिकारियों को परेशान करवाया बदले में ठीक है कि इनकी आतंकी कार्यवाहियों में मारे गए सबक जरूर मिल गया। साधु संतों को परेशान करने के बदले श्वानों की भांति बिछा दिए गए सड़कों पर.....

इराक...

पेज 1 से जारी

विश्व में सन 1980 से लेकर सन 2002 तक सबसे ज्यादा आतंकवादी संगठनों को पालने वाला, उनको आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सहयोग करने वाला अमेरिका और इँग्लैंड अब जब उसकी लपटों में घिरने लगे हैं तो उन्हें अब आतंकवाद विरोधी रुख अपनाना पड़ रहा है। मुम्बई के विस्फोटो, आतंकवादी घटनाओं में अमेरिकी विदेशमंत्री डलिना राइस अब पाकिस्तान पर दबाव बनाकर जांच में सहयोग की बात कर रही है। इसके पूर्व इंग्लैंड की बीबीसी और अमेरिकी सीएनएन सन 2001 तक लगातार उनके पक्ष में समाचार प्रस्तुत करते रहे हैं। यही अमेरिका था जिसने रूसियों को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए तालीबानों और ओसामा को पाला था। यही अमेरिका था जिसने सद्दाम हुसैन को भी 1970-80 के दशक में पाला था, फिर वही अमेरिका था जिसने 20 मार्च 2003 में ईराक पर सद्दाम हुसैन की सत्ता पलट हेतु आक्रमण कर लाखों को मौत की नींद सुला दिया। करोड़ों को घायल, करोड़ों को विस्थापित किया। ये है अमेरिकी आंतकवाद का असली चेहरा।

फिर भी खुशी हमें इस बात की है कि न केवल समय माया में वर्षों पूर्व लिखा सच सामने आया, वरन् दुनिया के गुण्डे अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने स्वीकारा कि ईराक पर आक्रमण कर उन्होंने भारी भूल की है। जिसका परिणाम आंशिकतौर पर मंदी के रूप में भोग रही है।

निःसंदेह यह अमेरिकी राष्ट्रपति बुश की चाल भी हो सकती है कि दुनिया में अपनी गिरती, बिगड़ती छवि को सुधारने, पुनः अपना वर्चस्व कायम करने के साथ ही आने वाले नए राष्ट्रपति ओबामा के यह स्पष्ट क़रने पर कि अमेरिका ईराक से अपनी और नाटो सैनिकों को वापसी करेगा। से पहले ही बुश जो कमाना था हथियार, कंपनियों, बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों से अब जब बिदाई का वक्त आ गया है तो सारी सैनाएं बुलवाएं, ताकि सारा श्रेय ओबामा की सुधारवादी नीतियों को न मिल जाए, इसलिए जाने से पहले भूल स्वीकारने में कुछ नहीं बिगड़ रहा है, जो करना था वो तो ईराक में कर ही डाला।

जातीय...

पेज 1 से जारी

स्वाभाविक है ऐसे भारतीयों को नौकरी से हटाने की अपेक्षआ अन्य को नौकरियों से हटाया जाएगा, जो अन्य कर्मचारियों, क्षेत्रीय गौरे-कालों को हजम नहीं होगा वो उन पर जलन से भी आक्रमण करेंगे, काम पर जाने से रोकेंगे। अर्थात भारतीयों को भी इस हिंसा का ज्यादा शिकार बनाया जाएगा, फिर भारतीयों का अन्य कई व्यवसायों पर जो कर्जा है। जिन्होंने में मेहनत से वहां अपने आप को स्थापित तो कर लिया है, पर उस क्षेत्र के अमेरिकी गोले-कालों को उनको नीचा दिखाने, अपना आक्रोश जाहिर करने के जो मौके वो वर्षों से तलाश रहे थे, इस नस्ल भेदी हिंसा में भी वे वहां पर इसके शिकार होंगे।

ओबामा का पिछला माता-पिता का इतिहास भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इसकी मां के दो पति थे, जो कैथोलिक ईसाई हैं। वही हाल पिता का है, जो परिवर्तित अफ्रीकी मुसलमान था, उसकी तीन पत्नियां थीं। स्वाभाविक है उस पर परिवार की निष्ठुरता, से परिवार से ही मिली है। जितना शक्ल व सीरत से सीधा दिखता है, वह वास्तव में उतना है तो नहीं जो सन 2009 के अंत और 2010 के प्रारंभ से सामने आना शुरू होगी, बेशक भारतीयों को उसने अपने स्टॉफ व मंत्रिमंडल में इसीलिए ही शामिल किया है कि वे मेहनतकश, बुद्धिजीवी वर्ग के हैं। यह भी भारतीयों के प्रति हिंसा को बढ़ावा देगा, इसके साथ का सच यह भी है कि ये ही उसके स्टाफ के भारतीय, भारतीय मूल के लोगों को इन नस्ल भेदी हिंसा से बचाने में भी पूरा सहयोग करेंगे। इसके विपरीत अमेरिकी पुलिस स्टेशनों में बैठे गौरे, काले इन भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार भी करेंगे नीचा दिखाएंगे। गोरे-गोरों को और काले-कालों को उस निचले स्तर पर सहयोग इन भारतीयों के साथ अवश्य ही भेदभाव करेंगे। और भारतीयों को अपमान के घूंट पीना ही पड़ेंगे। भारतीय दूतावास भी इनकी समुचित सहायता नहीं कर पाएगा।

एड्स...

पेज 8 से जारी

आखिर एड्स के पीछे इतना सब कुछ क्यों भाई, वहां कंडोम बेचने से मोटा माल, यौनाचार का सुख सब है। फिर पूरी केंद्रीय सरकार चाहती है कि इस देश में भी स्वच्छंद यौनाचार हो, थाईलैंड की तरह, यहां भी हर घर में वैश्या वृत्ति से कमाई हो, ये जनता के लिए कुछ भी न करे, सारा पैसा यहां से इकट्ठा कर विदेशी बैंकों में जमा कर दें।

थाईलैंड की अर्थव्यवस्था वैश्यावृत्तियों से ही चलती है। वहां की वैश्याओं से जो कर मिलता है, उससे शासन के खर्चे निकलते हैं। बेचारी सरकार इतना भय फैला रही है, कंडोम की आदत डालने के लिए अमेरिका के ईशारे पर स्कूलों में मुफ्त कंडों बंटवा रही है। स्कूलों कॉलेजों में यौनाचार सिखा रही है। फिर भी जनता की नजर सरकार से नहीं हट पा रही है। इसलिये वह अपने कुकर्मों षडयंत्रों में सफल नहीं हो पा रही है। इसलिए एड्स डे बनाम कंडोम डे भी मना रही है।

खाद्य सुरक्षा...

पेज 1 से जारी

बेरोजगार हो जाएंगे, यहां तक कि ठेले पर सब्जी बेचना भी प्रतिबंधित हो जायेगा।

- किसानों को अपनी सब्जी, अन्य कृषि फसलों को लाना, ले-जाने पर भी रु. 25 हजार न्यूनतम से अधिकतम रु. 5 लाख तक का दंड किया जा सकता है अर्थात इन बहुराष्ट्रीय कं. के एजेंट उससे खेत पर ही अपनी मनचाही कीमत पर माल खरीदेंगे।
- रिलायंस ने इस कानून को अपने हित में बनवाने के साथ ही पूरे देशभर में सब्जी बिक्री के बड़े-बड़े भंडारगृह खोल दिये है। कानून के पूर्ण अस्तित्व में आते ही सब्जी के ठेले या सड़क किनारे से नहीं मिलेगी केवल रिलायंस फ्रेश पर ही मिलेगी। उनकी मनचाही कीमतों पर।
- चायपान के ठेलों से लेकर, किराना, मिठाई, नमकीन, चाट, पकोड़ी तक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा दुकानें, ठेले, सब्जी भाजी की फुटपाथों पर लगी दुकानें तक सब बंद करनी पड़ेगी, अर्थात 5 करोड़ तक सीधे बेरोजगार हो जायेंगे।
- चाय-पान, नास्ता, भोजन तक सभी बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां के अधीन उनके फुटकर बिक्री केंद्रों से ही होगा उनकी मुंह मांगी कीमतों पर ही आम जनता को उपलब्ध होगा।
- बेशक इस खाद्य सुरक्षा एवं स्तर अधिनियम 06 को लोकसभा और राज्यसभा के बाद सर्वोच्च न्यायालय तक लागू करवाएंगे रु. एक हजार करोड़ से ज्यादा खर्च करके सबको खरीदकर 16/2/08 से लागू करवा दिया गया है। जिसमें रिलायंस ने ही पैसा खर्च किया।
- यह एक मात्र ऐसा अधिनियम होगा जो रक्त क्रांति और खूनी होली की शुरुआत करेगा।
- इस अधिनियम के लागू होते ही बाजार, मंडी की व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त करने का षडयंत्र और मुख्तः सारा कारोबार लियांस, आईटीसी की चौपाल व्यवस्था को सौंपने और लूट व वसूली का आगाज है।
- इस देश का दृश्य और श्राव्य मीडिया के मुस्तेदों को 3 वर्ष बाद भी अ, ब, स, द समझ नही आया, इस अधिनियम का श्वानों की फौज टुकड़े खाकर चुप है।
- इसका सबसे बड़ा लाभ सत्ताधीशों को अरबों रु. का कमीशन हर माह पूरे देश में मिल जाया करेगा, हर राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार के भुखेरों को जो भौंकने योग्य होंगे टुकड़े फेंकना ही पड़ेंगे।
- यह लोकतांत्रिक कल्याणकारी सरकार का सबसे विकृत और घिनौना रूप होगा।
- इससे खाद्य उद्योग में लगे छोटी फैक्ट्रियों, मिलो, आदि से अप्रत्यक्ष रूप से 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो जायेंगे।
- इसमें खाद्य सुरक्षा के नाम पर वर्तमान का खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत स्थापित खाद्य एवं औषधि प्रशासन मेंखाद्य को बंद करके खाद्य सुरक्षा आफत होगा, जिसके अंतर्गत एक नमूने के चार नमूने बनाकर एक नमूना उस फैक्ट्री/खाद्य विक्रेता को भी देना होगा, जिसकी वो मनमाफिक तरीके से जांच करवाकर रिपोर्ट न्यायालय में मुकदमा लगाने पर प्रस्तुत कर सरकारी नमूने को झुठलाकर भी बिना दंड दिये भी दंड पेल सकता है।
- इस नियम के अस्तित्व में आने पर दीर्घावधि में सब खाद्य पदार्थ पूरे भारत में नकली बनाने के उद्योगों की भरमार हो जायेगी, क्योंकि अधिकतम जुर्माना रु. 5 लाख देना है और सजा की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो कौन डरेगा फिर सरकारी डेरियां भी पॉलिथीन का और यूरिया खाद व डिटर्जेंट पावडर का दूध, नकली घी, नकली दूध की मिठाईयां तक बकायदा बोर्ड लगाकर बेचने की पात्रता आ जाएगी। सारा असली माल यूरोप निर्यात कर दिया जायेगा।
- इस कानून के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी या प्राधिकरण का अध्यक्ष रिलायंस, आईटीसी, पेप्सी, कोक, हिंदुस्तान लीवर की ही पसंद की कठपुतली होगा, उसके सदस्य इन्हीं कंपनियों के चेलेचपाटी।
- भूखे कमीशन खोर कांग्रेसी मंत्रियों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अंबूमणि रामदास, नागरिक आपूर्ति मंत्री से प्रधानमंत्री मनमोहन तक सारे भेड़ियों ने करोडों को बेरोजगार करने, पूरे देश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ सौंपकर आम आदमी का चायपान से लेकर मुंह से निवाला छीनने की पूरी तैयारी कर ली है। ये है इन भूखे कमीशन खोर भेड़ियों की लोकतांत्रिक सरकार जो लगभग 10 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार कर देगी।
- नई दवा नीति के लागू होने स पूरे देश में 5 हजार से ज्यादा छोटी इकाइयां बंद कर दी गई, सारा व्यापार दवा उद्योग का अब बहुराष्ट्रीय कं. के हाथ में है, वैसे भी खाद्य उद्योग भी बहुराष्ट्रीय कं. के हवाले कर 120 करोड़ की आबादी में यदि 20 करोड़ तक भी बेरोजगार हो जाये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 40 करोड़ के हाथ एक वक्त का भोजन के लिए महंगाई के कारण तरस जाये तो भी इन हरामखोरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
- इस कानून के संबंध में सभी राजनैतिक दलों को खरीद लिया गया, कोई भी दल इसके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला। कम्युनिस्टों को जो मजदूरों की पार्टी बताता है शायद सब सत्ता के मद में मदहोश होकर ऊंघ रहे थे, कांग्रेस के साथ भाजपा, बसपा, सपा कम्युनिस्ट, सारे भुखेरे रिलायंस के डाले हुए टुकड़े चबाने में व्यस्त थे।
- भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और उसके स्टाफ में बैठे दिग्गजों को भी भारी धन दिया गया। इन बहुराष्ट्रीय कं. ने जिसके कारण इसका कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, वैसे भी उस पद पर बैठी उस रबर की बुढ़िया रूपी मुद्रांक इसी उपयोग के लिए बैठाया गया था, ताकि आंख मींचकर राष्ट्रपति का स्टाम्प लगाकर वह हस्ताक्षर करती रहें।

म.प्र. वाणिज्य कर सूचना आयोग के आदेश की धज्जियां

भ्रष्ट सूचनाएं न देने, देते हैं व्यर्थ दलीलें

इंदौर। सूचना के अधिकार में जानकारी देने के मामले में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा निकम्मा सिद्ध हुआ है म.प्र. वाणिज्य कर विभाग,यहां बैठे धूर्तो मक्कारों और जालसाजों की फौज, किसी भी कीमत पर सूचना नहीं देना चाहती। क्योंकि यहां बैठे अधिकारी कदम-कदम पर ढेर सारी जालसाजियां करते हैं, इसलिए उनको सूचना के अधिकार में जानकारी देने पर अपनी नौकरी जाने से लेकर जेल की हवा खाने तक सब कुछ संभावित दिखता है।

ऐसे ही एक आवेदन उपायुक्त वाणिज्यिक कर एंटी इवेजन ब्यूरो इंदौर ए. को अक्टूबर 07 में दिया गया था। जानकारी न देने पर उसकी अपील की गई जो विभाग के ही बड़े अधिकारियों को दी जाती है, कैसे अपने अधीनस्थ की जानकारी दें, इसीलिए द्वितीय और अंतिम पील की गई, वहां 16/10/08 का आदेश आने के बाद भी भ्रष्ट श्रीवास्तव ने जानकारी न देने के लिए जो दलील दी है वो अक्षरशः निम्नानुसार है-

कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, एण्टी इवेजन ब्यूरो इंदौर-ए

विस्तार कार्यालयः 8वां तल, चेतक चेम्बर्स, आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर

क्रमांक 2/08/लो.सू.अ./एईबी/इंदौर-ए/2 इंदौर, दिनांकः 10.11.08

प्रति,

श्री अजमेरा एस.पी. कुमार

299 अम्बेडकर नगर

इंदौर

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन

संदर्भः- मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिला 58, अरेरा हिल्स, भोपाल ज्ञाप क्रमांक ए-0159/रासूआ/ 07-02/इंदौर/2008/924, दिनांक 16.10.08

संदर्भित ज्ञाप के साथ द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 159/08 श्री अजमेरा एस.पी. कुमार विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यकर विभाग, एण्टी इवेजन ब्यूरो विंग-ए इंदौर में सूचना आयुक्त द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 8.9.08 की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 18.10.08 को प्राप्त हुई है। इस प्रकरण से संबंधित आपके विषयांकित आवेदन नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आपके द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भूमिका में यह उल्लेखित है कि ''ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाए।'' यहां पर सूचना के पूर्व कतिपय शब्द का उल्लेख किया गया है। इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि इसमें विशिष्ट प्रकार की सूचनाएं सम्मिलित हैं, न कि सभी प्रकार की अनगिनत सूचनाएं।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध से संबंधित है। धारा 6 (1) में उल्लेखित है कि '' मांगी गई सूचना की विशिष्टियों को विनिर्दिष्ट करते हुए'' आवेदक आवेदन प्रस्तुत करेगा, अतः चाही गई सूचना सामान्य प्रकार की न होकर विशिष्ट उल्लेख के साथ होना चाहिए। आपकी ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 6 के प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की कंडिका 6 में चाही गई जानकारी के विवरकण में किसी भी जानकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदन के साथ संलग्न 10 रुपए के स्टाम्प में वांछित जानकारी का उल्लेख किया गया है। आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संलग्न नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प की कंडिका 1 एवं 2 में चाही गई सूचनाएं सामान्य प्रकार की तथा अनिश्चित एवं अत्यधिक विस्तृत है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 सूचना का प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है। धारा 8 (घ) के अंतर्गत ''सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा, सम्मिलित हैं जिसका प्रकटन किसी पर-व्यक्ति की प्रतियोगात्मक स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का सामाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन वृहत्तर लोकहित आवश्यक करता है।'' एवं धारा 9 (ज) के अंतर्गत ''सूचना जिसके प्रकट करने से अन्वेषण या..... की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाएगी'' को किसी भी नागरिक को प्रदत्त करने की बाध्यता नहीं रखी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन के संलग्न नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प की कंडिका 1 एवं 2 में चाही गई मांगी गई सूचनाएं व्यवसाइयों पर विभाग द्वारा डाले गए छापों से एवं परिवहनकर्ताओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित है। इनमें से छापों से संबंधित प्रकरणों में पश्चातवर्ती अन्वेषण/सूक्ष्म जांच (स्क्रूटनी) कर निर्धारण कार्यवाही अभी लंबित है, अतः यह सूचना दिए जाने से पश्चातवर्ती कार्यवाही प्रभावित हो सकती है, जिससे शासन को राजस्व हानि की स्थिति निर्मित हो सकती है। इसके अतिरिक्त छापों एवं परिवहनकर्ताओं पर की गई कार्यवाही में संबंधित व्यवसाइयों एवं परिवहनकर्ताओं के नाम, पते एवं अन्य विवरण की सूचना दिए जाने से संबंधितों की वाणिज्यिक विश्वसनीयता एवं प्रतियोगात्मक स्थिति को नुकसान पहुंच सकता है।

नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प की कंडिका में यह जानकारी भी चाही गई है कि कर अपवंचन से संबंधित प्रकरणों में कितना कर संग्रहित किया गया है, इन प्रकरणों में ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार पश्चातवर्ती अन्वेषण/ सूक्ष्म जांच (स्क्रूटनी)/कर निर्धारण कार्यवाही अभी लंबित होने से कर संग्रहण की स्थिति अभी निर्मित नहीं हुई है, अतः इस बिन्दु पर जानकारी भी विभाग को ज्ञात नहीं है।

अतः ऊपर दर्शाए गए कारणों से आवेदन के संलग्न नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प की कंडिका 1 एवं 2 में चाही गई सूचनाएं आपको दिया जाना वैधानिक एवं व्यावहारिक प्रतीत नहीं होने से वांछित जानकारियां उपलब्ध कराई जाना संभव नहीं है।

आवेदन के संलग्न नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प की कंडिका 3 में चाही गई जानकारी संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः उक्तानुसार एक

(रवीन्द्र श्रीवास्तव)
उपायुक्त, वाणिज्यिक कर,
एंटी इवेजन ब्यूरो, इंदौर-ए

हिन्दुओं का खून, पानी

असली आतंकियों को बचाना, संतों को प्रताड़ना

कांग्रेसी गिरोह की जालसाजियां अपने पाप धोने, मुस्लिम वोट बैंक के लिए

वर्तमान में महाराष्ट्र जहां कांग्रेसी शासन है, आतंकवाद के नाम पर असली आतंकवादियों के बचाने और साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, फिर अमृतानंद, दयानंद पांड्ेय व अन्य अनेकों को एटीएम के माध्यमसे कोई भी कारण बनाकर उठाया जा रहा है। नार्को टेस्ट स्वामी अमृतानंद, कर्नल पुरोहित क्या राज उगले जानबूझकर अपनी तरह से अपनी वाहवाही लूटने, हिन्दुओं को बदनाम करने का ही पूरा षड्यंत्र है।

साध्वी प्रज्ञा के चार-चार परीक्षण हुए जब कुछ भी सामने नहीं आ रहा है, फिर जेल में बंदकर नार्को टेस्ट के बहाने एटीएस के पुलिसकर्मियों द्वारा उसके साथ मारापीटी व अन्य जो उनसे अधिकतम करते बन रहा है किया जा रहा है। कुल मिलाकर सोनिया का ईसाई संस्थाओं को अपने कार्य करने से रोकने का बदला इन हिन्दु साधु-संतों से इस प्रकार प्रताड़ित कर लिया जा रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कांग्रेस अपने सिर पर आतंकियों के संरक्षण और गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के कांडों पर पर्दा डालकर मीडिया में लगातार होने वाले इन प्रकाशनों से अपने पाप धोना चाहती है।

पिछले 35 वर्षों से कांग्रेस मुस्लिम वोटो और फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण कर जिस प्रकार से भारत में पुनः जातीय दंगों को भड़का कर सत्ता हथियारने का षड्यंत्र रच रही है। इस प्रकार से लगातार मीडिया में जम कर उछाला जा रहा है। जबकि सत्ता यह है कि 78 से ज्यादा राज्यों के चुनावों में कांग्रेस इस बहाने मुस्लिम वोटों को बटोरने का खेल खेल रही है, ताकि उस पर ऐतिहासिक आतंकवादीह ोने का मतदाताओं के मस्तिष्क से प्रभाव कम हो सके।

कांग्रेस सिमी इंडियन मुजाहिद्दीनों के राष्ट्रव्यापी विस्फोटों में हर स्थान पर उसका हाथ होना सिद्ध होने के बाद भी उन पर सीधी कार्यवाही नहीं ही कर रही है। दूसरी तरफ अफजल गुरु को सांसद हमला कांड में मौत की सजा होने पर भी बिरयानी मस्तानी खिला पिला कर पाल रही है। जब कोई नेता उसकीतरफ बोलता है तो चुप हो जाती है। मनमोहन, सोनिया और उसके कांग्रेसी गिरोह जिसमें अर्जुन जैसे शातिर, कमलनाथ, प्रणव, दूसरे दलों के मुलायम, अमरनाथ, के साथ लालू ने तो सिमी पर प्रतिबंध जो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार लगाया गया है, को भी हटाना चाहते हैं, जबकि हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचारों के मामले में अगर बजरंगी अगर प्रदर्शन करते हैं, या ईसाई मिशनरियों को ईसाइयत फैलाने से रोकते हैं जो कि कानूनन जुर्म और अवैध होने के बाद भी यदि विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आवाज उठाता है तो उसका बदला प्रताड़ना और बदनामी किस प्रकार की जाती है। उसका ज्वलंत प्रमाण है साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, अमृतानंद और पांड्ये के साथ ही बजरंग दल, विहिप रा.स्व. से. संघ के पदाधिकारियों की प्रताड़नाएं जो इन दिनों चुनावों को प्रभावित करने को दृष्टिकोण से प्रकाशित करवाई जा रही है।

सारा कांग्रेसी गिरोह यह जानता है कि भारत का हिन्दू समाज न तो एकजुट है, नही इसकी शिराओं में खून है। इसका खून पानी है।ये इसकी सहस्त्रों वर्ष पुरानी कहानी है। इस पर महाभारत काल से अभी तक सबने इसीलिए न केवल राज किया वरन् गुलाम बनाकर भी रखा, इसकी इस कमी को दूर करने का जिम्मा यदि विहिप और बजरंग दल ने उठा रखा है। तो क्यों न इसी को प्रताड़ित करो ये साधु, संत, साध्वीयां न हो सके इसलिए इन साधु संतों, साध्वीयों को आतंकवादियों की छवि में प्रस्तुत करो, ताकि इसका मान,सम्मान न केवल समाप्त हो जाए हिन्दू बिखर जाए और इनसे नफरत करने लगे। इस प्रताड़ना, मीडिया में उछाले जाने और बदनाम करने के षड्यंत्र के पीछे उपरोक्त कहानी ही है।

हमारी करप्शन इंडिया पर करप्ट इंडिया की साइटो ने साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी और नार्को टेस्ट के बहाने प्रताड़ना के समय ही अपनी साइटों से इस षड्यंत्र की सच्चाई प्रगट कर दी थी, जिसे सुषमा स्वराज ने भी इन शब्दों में प्रस्तुत किया-

प्रज्ञा का मामला चुनावी स्टंट

इंदौर। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुषमा स्वराज ने साध्वी प्रज्ञा के मामले को चुनावी स्टंट बताते हुए मुम्बई एटीएस को चेताया है कि वह भगवाधारी साधु सन्यासियों और हरी वर्दी पहनने वाले फौजियो पर संदेह के आधार पर कारवाई करने से पहले अच्छी तरह ठोंक बजा ले देश के लोगों की दोनो मे गहरी आस्था है। प्रेस से मिलिए कार्यक्रम मे स्वराज ने कहा साध्वी को लेकर किया जा रहा स्टंट चुनाव खत्म होते ही बंद हो जाएगा क्या कांग्रेस देश को बताना चाह रही है कि साध्वी लश्कर जैश और सिमी से भी खतरनाक है दोष सिद्ध होने के बाद भी अफजल की आवभगत की जा रही है दूसरी तरफ साध्वी का बार बार नार्को टेस्ट करवाया जा रहा है क्यो कि जाँच एजेसियां जैसा चाहती है वैसा कुछ नही निकल रहा।

एटीएस ध्यान रखे भगवा के साथ वर्दी के लिए देश मे सम्मान है-सुषमा स्वराज्य

चुनाव खर्च - विकलांगों के नाम, बना रहे विकलांग

47209 मतदान केंद्रों पर बनाए गए रपटों में भ्रष्टाचार

म.प्र. 25 व 27 नवम्बर को 08 को जो मतदान किया गया उनमें पूरे म.प्र. में 47209 मतदान केंद्रों पर मतदान हेतु विकलांगों के लिए मतदान केंद्रों पर जहां पर जीने चढ़कर मतदान केंद्रों तक जाने की व्यवस्था थी उन मतदान केंद्रों में जीने को पाटकर उस पर रपट बनाए गए थे, जिनमें प्रति रपटा रुपए 10,000/- खर्च किए गए।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जो सरकारी कार्यालयों में रपटे बनाए गए जो कि शहरी क्षेत्रों में थे। प्रति रपट पर रुपए 10,000/- में से मात्र रुपए कहीं रुपए 3000 से रुपए 5000/- खर्च भी किए गए, परंतु निजी शैक्षणिक संस्थानों में गांवों के प्राथमिक, माध्यमिक, शिक्षण शालाओं में ऐसे रुपए 5000 से रुपए 1000/-तक खर्च करके ऐसेर पटे बनाए गए जो 35', 45' के कोण पर बनाए हैं। पूरे मुख्य द्वार पर रपटे बनाने से पाठशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को न केवल चढ़ने में परेशानी उठानी पड़ रही है, साथ ही ऐसे हजारों स्थानों पर कुल मिलाकर विकलांग सायकिल लेकर भी नहीं चढ़ पाए, अंत में उन्हें सायकल छोड़कर हाथों के बल या लकड़ी टेककर ही चढ़ना पड़ा। सूचनाओं के अनुसार ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं तो तात्कालिक व्यवस्था कई ईंटों की मिट्टी से भराई कर ऊपर सीमेंट का पलस्तर कर दिया गया, अर्थात रुपए 500 से 1000/- खर्च करके बाकी पैसा ठेकेदार और काम करवाने वाली एजेंसी व जिले में चुनाव अधिकारी द्वाराड कार लिया गया। इस प्रकार 47209 केंद्रों पर रुपए10000 के हिसाब खर्च किए रुपए 47,20,90,000/- में से 50 जिलों के 230 विधान सभा क्षेत्रों में मात्र काम हुआ लगभग रुपए 10 से 15 करोड़ के बीच बाकी रुपए 32 से 35करोड़ चुनाव व आयोग और उनके जिलाधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा मिलकर हजम कर लिया गया।

इन रपटों पर अब रोज ही न केवळ 60 से 80 लाख विद्यार्थी व शिक्षकों को चढ़ने उतरने में परेशानी हो रही वरन् ठीक से चढ़ उतर न पाने के कारण बच्चों को भी हर दिन चोटें लग रही है। यही हाली पूरे प्रदेश के 50 से 50 हजार से ज्यादा कार्यालयों के कर्मचारियों के साथ भी घट रहा है।

विधानसभा चुनाव 08

म.प्र., राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, दिल्ली व कश्मीर

भाजपा, कांग्रेस के बागी बिगाड़ेंगे समीकरण

टिकिट वितरण का घमासान, बगावत अपने ही करेंगे बर्बाद

भारत के छह राज्यों में चुनाव घोषित हो गए हैं। जिसमें म.प्र., छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, गोवा और जम्मू-कश्मीर राज्य हैं। म.प्र., छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस ही मुख्य रूप से चुनाव दंगल में शामिल हैं। इन चारों राज्यों में दोनों ही पार्टियों को अपने ही कार्यकर्ताओं से टिकट वितरण को लेकर भारी घमासान हुआ है। म.प्र. में हीहर सीट पर 5 से 10 प्रबल दावेदार थे। साथ ही पूर्व के विधायक या कम अंतरों से हारे हुए प्रत्याशी भी थे, जिसमें भाजपा ने अधिकांश पूर्व के विधायकों को टिकट दिया तो कांग्रेस ने अधिकांश पूर्व विधायकों को टिकट तो दिया ही साथ में उन कम अंतर से हारे हुए प्रत्याशियों पर भी पुनः कई जगह दांव खेला गया।

बहुत थोड़े फेर बदल के साथ यह स्थिति पूरे छट राज्यों में लगभग एक जैसी है। भाजपा, कांग्रेस दोनों ही अंदरुनी कलह, बगावत और टिकट न मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में या छोटे दलों में शामिल होकर टिकट प्राप्त कर चुनाव मैदान में आ खड़े हुए हैं। जो बेशक हजारों की तो दूर सैकड़ों के अंतर से भी जीतना मुश्किल कर देगी।

सत्ता में बैठे विधायकों और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार करने के ढेरों आरोप न केवल दिल्ली, म.प्र., छ.ग., राजस्थान से लेकर गोवा और जम्मू-कश्मीर में भी है। उन्हें हटाने की मांग के साथ नए चेहरे। लोग भी चुनाव लड़ना चाहते थे। स्वभाविक सी बात है कि दोनों ही दल इस बात से परेशान है।

चार राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य सभी दलों की गहरी पकड़ इतनी नहीं कि वो कोई बड़े फेरबदल कर सकें। चुनाव कर्नाटक में भी होना है। वहां पर भी भाजपा जो वर्तमान में सत्ता में है को साथ ही सपा और कांग्रेस मुख्य चुनाव दंगल में है पर ये चुनाव अभी दूर है।

अब जबकि छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुका है 60% वोटिंग हुई पर भी कांग्रेसी शासन के भ्रष्टाचार और लूटखसोट के तांडव से त्रस्त होकर जिस नक्सलवाद का जन्म हुआ 100 से ज्यादा वोटिंग मशीन छीन कर भाग चुके हैं। कांग्रेस संयुक्त रूप से जिस चांद पर यान पहुंचाने को उपलब्धि बता कर गिना रही है, स्पष्ट है कि वो इस उपलब्धि को अपनी पार्टी की सम्पत्ति और उपलब्धि का हिस्सा बता रहे हैं, जबकि वो योजना अटल बिहारी वाजपेयी की व पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की थी। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जिस राष्ट्र की कुल आबादी का 10% एक वक्त के भोजन से गुजारा कर रही हो, 10% जनता को दो वक्त मुश्किल से भोजन मिलता हो, चांद पर झंडे, डंडे गाड़ने से क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हम समृद्धि के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हर भूखे को दो वक्त की रोटी और हर बेरोजगार को कार्य मिल चुका है। पर ऐसा तो कदापि नहीं हो रहा, फिर जनता क्या हराएगी, जिताएगी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी व अन्य दल उनको हराने जिताने की जिम्मेदारी जिन कार्यकर्ताओं पर है सच्चे अर्थों में अपने ही विश्वासघाती ज्यादा घातक हो रहे हैं।

जहां कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में बसपा की माया के शार्गिद सेंध लगा रहे हैं। वहीं भाजपा में भाजपा से अलग हुई पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की भाजश उसके उम्मीदवार सेंध लगा रहे हैं। बेशक उमा भारती की थोड़ी बहुत पहुंच पकड़ केवल म.प्र. में ही दिखती है बाकी अन्य राज्यों में उमा भारती की भाजश की न पहुंच पकड़ है न धरातल। इसलिए भाजश को मप्र में छोड़कर उमा भारती से राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक में कहीं कोई खतरा नहीं है।

उमा भारती ने म.प्र. में अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार खडे किए हैं जो जीते न भी जीते फिर भी उसे 10% तक भाजपाई उम्मीदवारों के वोट अवश्य ही कांटेंगे जो 27 नवम्बर को स्पष्ट हो जाएगा।

जहां तक बसपा का सवाल है तो बसपा के उम्मीदवार न केवल म..प्र. में वरन राजस्थान में भी कांग्रेस उम्मीदवारों के हार-जीत के अंतर को कम अवश्य कर देगा।

सभी राज्यों के चुनावों में हर उम्मीदवार को विपक्षी से उताना ज्यादा भय नहीं लग रहा है, जितना अपनी ही पार्टीयों के बागी और जिन्हें उम्मीदवार होने का गौरव नहीं मिल पाया उन नेताओं से ज्यादा घात का भय सता रहा है। कांग्रेस ने ऐसे सैकड़ों नेताओं और उनके चेले चपातियों को बाहर का रास्ता दिखाया अवश्य है, परंतु भविष्यही निर्धारित करेगा, कि कौन कितना अपने आप को सफल सिद्ध कर पाएगा।

खंडवा में पूरा प्रशासन भ्रष्टमंत्री शाह के इशारे पर नाचा

समय माया के दो पत्रकार शाह के इशारे पर गिरफ्तार

आई.जी., आयुक्त, मुख्य सचिव, चुनाव आयुक्त ने नहीं सुना, केवल डीजी राउत ने ही कहा मालूम करता हूं

चुनाव आचार संहिता का जितना नाटक बाहरी तौर पर दिखाया जा रहा था और दिखाया गया, उसकी सत्यता की बानगी खंडवा जिले के जिलाधीश सी.बी. सिंग, इंदौर के आयुक्त बी.पी. सिंग, इंदौर रेंज के महानिरीक्षक अनिल कुमार, म.प्र. के मुख्य सचिव राकेश साहनी, मुख्य चुनाव आयुक्त, ए.व्ही. सिंग ने हमारे भोपाल के पत्रकारश्री एस.के. भारद्वाज और खंडवा के प्रतिनिधि श्री सुशील परिहार को दिन में 3 बजे, विजय शाह ने खंडवा जिले की हरसूद तहसील के खालवा थने की रोशनी चौकी पर 26/11/08 को बिना किसी कारण के गिरफ्तार करके दिखवा दी।

जबकि ये दोनों त्रकार भ्रष्ट आपराधिक अय्याश भाजपा के वनमंत्री, विजय शाह द्वारा अपने हरसूद क्षेत्र में ट्रकों से बुलाई और बंटवाई गई शराब, कंबल, स्वेटर का पीछा करते-करते रोशनी चौकी पर शिकायत करने पहुंचे थे, बेशक विजय शाह के भ्रष्टाचार के कारनामों से भरी। छपी हमारे पत्रकार एस.के. भारद्वाज की स्वराज न्यूज की कुछ प्रतियां उनके पास थी। जो उन्होंने बांटी थी। इससे बौखलाकर व~ इनके पीछे पड़ा हुआ था। जैसे ही ये चौकी में सूचना देने पहुंचे, उसने वहां के प्रभारी महले को गालियां बकते हुए 27/11/-08 को मतदान समाप्त होने तक बैठाने के लिए कहते हुए गालियां बककर किसी भी तरह से प्रकरण बनाकर बैठाए रखने के लिए दबाव डाला। जिससे वहां इन पर धारा 188 का मुकदमा दूसरे दिन 27/11/08 अनेकों विजयशाह के समर्थकों से झूठे बयान लेकर व शिकायतें लेकर दर्ज करवाया गया।

इंदौर। पूर्व सरकार के महाभ्रष्ट, अय्याश, वनों की अवैध कटाई करवाने, वन विभाग के अधिकारियों से जमकर वसूली करने वाला वन मंत्री विजय शाह खंडवा का प्रभारी मंत्री भी था। जिसके भ्रष्टाचार के सैकड़ों कारनामें वन उजाड़ने, अवैध कटाई करवाने, आदिवासियों के नाम से 1 लाख गैस कनेक्शन भारत पेट्रोलियम कं. से लेने और उं अपनी गैस एजेंसी विजयशक्ति के माध्यम से रुपए 4500 से 6000 में खंडवा में व अन्य अपनी छोटी उप वितरक बना कर बेचने के किस्से, कहानियां इसकी अय्याशी की सीडी, इसके गीता भवन चारौहे पर मनोरमा गंज के अपार्टमेंटों में अय्याशी, पलासिया से लगे भवन में एक उद्योगपति की नवयौवना के साथ सके पुत्र व उसके मित्रों की बलात्कार और सामूहिक यौनाचार के किस्सों ने शहर के अखबारों की फिजा में सुर्खियां बनाई हैं। जिसे अपने मंत्री पद के प्रभाव का दुरुपयोग कर दबाया गया।

इन सबकी गहराई में जाएं तो खोजबीन करने वाले हमारे जांबाज पत्र सुशील परिहार ने जब सच्चाइयां प्रकट करते हुए इसकी शिकायतें कई जगह कर दी तो इसने अपना सत्ता के मद में चूर हो अपना दानवी रूप दिखाते हुए उस पर कई झूठे मुकदमें लगवा कर उसे 4 महीनों से ज्यादा तक अंदर करवा दिया। खंडवा के सारे वकीलों को धमकाकर उसकी न तो जमानत होने दी न उसका केस लड़ने के तैयार हुआ। अंत में इंदौर के दीक्षित वकील ने जब उसका प्रकरण हाथ में लिया तो उसे भी रुपए 50000/- का लालच देकर रोका गया।

अर्थात यह कुकर्मी भाजपाई मंत्री किस हद तक परिहार के पीछे पड़ा है, यह स्पष्ट करता है। यही दुर्भावना पूर्ण कार्यवाही शाह ने आचार संहिता लगे होने के बाद भी अपने बैठाए हुए थाना प्रभारी खालवा से करवा तो दी ही है।

इस गिरफ्तारी ने तंत्र के उन शासकीय श्वानों की रोशनी, खालवा से लेकर खंडवा, भोपाल और दिल्ली तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बालकृष्णन की सच्ची तस्वीर दिखा कर यह ये वो सफेदपोश शासकीय गिरोह है जो कदम-कदम पर अपने ही पद, कानूनों का माखौल उड़ाते हुए धन का गुलाम बन कर कैसे नाचता है।

हमारे पत्रकार द्वय की गिरफ्तारी की भनक हमारे कार्यालय को रात में 1 बजे श्री सुशील परिहार की धर्मपत्नी ने दी, क्योंकि चौकी प्रभारी महले ने उनके मोबाइल भी छुड़ा लिए थे। खबर लगते ही सबसे पहले इंदौर रेंज के प्रभारी महानिरीक्षक अनिल कुमार से जब श्री अजमेरा ने बात की तो पुलिसिया अंदाज में जवाब मिला कि हां, उन दोनोंको अरेस्ट किया है, धारा 188 में वो उम्मीदवार के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहे थे।

जब उनसे कहा गया कि वो सूचना देने गए थे, अवैध शराब, स्वेटर और कंबल बांटने की तो उनका कहना था कि नहीं वो वहां पत्रिका बांट कर माहौल बिगाड़ रहे थे जो धारा 188 में आता है। उनकी जमानत करवाकर छुड़ा लेना। जब यही बात इंदौर के संभागायुक्त से पूछी गई तो उसका कहना था कि मुझे नहीं मालूम, बताने के बाद भी कि उनको गिरफ्तार कर लियागया है तो इस इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारी ने नाम के अनुकूल कृत्य करते हुए फोन काट दिया। अर्थात विजय शाह के मंत्रित्व में बिके हुए इन दोनों को जब आचार संहिता याद नहीं आई, जबकि संभागायुक्त पदेन संभाग का चुनाव अधिकारी भी था, इसके विपरीत वह मंत्री का गुलाम बनकर से ही निभा रहा था।

इसके पूर्व हम अपनेपाठकों को बता दें कि चुनाव आचार संहिता लगे होने के बाद भी पूरा वन विभाग जिलाधीश, पुलिस विभाग, खंडवा ने आडवाणी की सभा के लिए न केवल सरकारी गाड़ियों का खुलकर उपयोग किया, भोजन, पानी से लेकर धन तक जटाया गया। क्योंकि मंत्री रहते हुए विजय शाह ने चारों तरफ अपने ही चेले चपाटियों को जिसमें जिलाधीश सी.बी. सिंह भी शामिल हैं बैठा दिया था। जो उसकी अंधभक्ति में लगे रहकर विजय शाह का चुनाव प्रबंधन संभाल रहे थे। आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर उसे मजाक बना दिया था. पूरे खंडवा प्रशासन, पुलिस और वन विभाग ने। चूंकि, कांग्रेस का उम्मीदवार न केवल कमजोर था, वरन वह चुनावी प्रबंधन तो जानता ही नहीं था जो इन सबके बारे में पूछताछ करता।

इसके बाद मुख्य सचिव राकेश साहनी के निवास पर फोन लगाया तो वो किसी पार्टी में मजे कर रहे थे। उसके पी.ए. को बता कर अपना चलित दूरभाष नम्बर दे दिया गया। परंतु उनका फोन नहीं आया, क्योंकि वो तो पहले ही श्री अजमेरा के सूचना अधिकार केप त्रों से पीड़ित थे। वही हाल मुख्य चुनाव आयुक्त ए.व्ही. सिंग का भी था। ुचनाव की रात शायद वो अपना तनाव दूर करने के लिए किसी पार्टी में गए थे जैसा कि निवास से बताया गया, उनको भी घटना बताई गई, मोबाइल नम्बर दिया गया पर वो भी जवाब नहीं आया।

घटना के संबंध में फिर प्रदेश के पुलिस के महानिदेशक श्री राउत के घर पर फोन लगाया, उन्होंने बात की घटना बताई गई तो उन्होंने भर बोला कि मैं देखता हूं।

इसके बाद दिल्ली स्थित मुख्य सूचना आयुक्त बालकृष्णन से बात की गई तो उसका कहना था कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। अर गिरफ्तारी की गई है तो जमानत देकर छुड़वा लीजिए। ये है निष्पक्ष चुनाव की और आचार संहिता के पालन की छोटी सी बानगी।

बेशक समयमाया ने चुनाव परिणाम आने के बाद दोनों पत्रकारों को खुली छूट दे दी है कि वो कानूनी कार्यवाही करें। इसके पूर्व में आदिवासी छात्रावासों में चल रहे भ्रष्टाचार, विद्यार्थियों के शोषण, स्तरहीन भोजन सामग्री के संबंध में लगातार शिकायतें मिलने के बाद जब ये दोनों उसके अधीक्षक से पूछताछ करने पहुंचे तो विजय शाह ने 1000/- मांगने का आरोप लगवाकर और जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगवा कर भी थाने में शिकायत करवाई थी। यदि हमारे पत्रकार ब्लैकमेलिंग करने और धन कमाने का ही शौक पालते या करते तो न तो श्री सुशील परिहार आशापुर के झोपड़े में रहते, न ही श्री अजमेरा जो मुख्य सम्पादक हैं रुपए दो हजार के छोटे से मकान में अम्बेडकर नगर की गंदी बस्ती से अपना घर और कार्यालय चलाते।

बेशक सच्चाई और गरीबों की लड़ाई लड़ना कितना टेड़ी खीर है जो करतेह ैं वो जानते हैं, साथ ही विजय शाह के भ्रष्टाचार, जालसाजियों, वनों की बर्बादी पर वसूली करते, उसका प्रचार करते जैसा कि पुलिस खालवा ने आरोप लगाये थे कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके पूर्व भी विजय शाह ने हमारे पत्रकार सुशील परिहार की हत्या के लिए कई बार प्रयास किए हैं। उसको डराने धमकाने, पुलिस से उठवाने के तो अनेकों प्रयास किए जा चुके हैं। उसके एक भाई की हत्या हरसूद से भोपाल लाते समय चलती ट्रेन से धक्का देकर करवा दी गई। इसके साथ ही 26 नवम्बर 08 की रात को श्री अजमेरा सबको फोन नहीं करते तो पुलिस चौकी रोशनी में भी पूरी तैयारी थी ये है भाजपा की भ्रष्टाचार के विकास और उसके पूर्व के चरित्र की सच्चाई, ऐसे होते हैं निष्पक्ष चुनाव। तो सरकारी अधिकारी, मंत्री ब्लैक काम करते ही क्यों हैं? जो ब्लेकमैलिंग की नौबत आए। फिर ब्लैकमेलिंग का उद्देश्य धन कमाना और अपने काम निकलवाना होता है। अगर समय माया के पत्रकार यही करते तो उनका महीने में एक अखबार अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की खबरों से भरा नहीं होता। उनका काम क्षेत्रीय खबरों से ब्लैकमेलिंग कर पैसा कमाना होता।

दूसरा मंत्री विजयशाह ने हमारे भोपाल के पत्रकार सतीश भारद्वाज को जान से मारने की धमकी दी, रोशनी पुलिस चौकी में कि तुझे घर से उठवा कर निपटा दूंगा। कल कोई घटना घटती है तो विजय शाह ही उसका जिम्मेदार होगा।

व्यापारिक औद्योगिक सहकारी बैंक लि., इन्दौर
महादेव शाहरा सभागृह, नई अनाज मंडी, संयोगितागंज, इन्दौर
फोन : 2477755-2477766, 4084827
सहकारिता सप्ताह पर हार्दिक अभिनंदन
गोपालदास अग्रवाल
अध्यक्ष
मोहनलाल सैनी — उपाध्यक्ष
महेन्द्रसिंह राजपाल — प्रबंधक
श्रीमती सीमा मंगल — उपाध्यक्ष
-संचालकगण-
श्री मनोज काला, श्रीमती किरण बागड़ी, श्री अरूणकुमार अग्रवाल, श्री सुकुमाल सेठी
श्री रामेश्वरलाल असावा, श्री प्रकाश व्होरा, श्री कमल अग्रवाल, श्री नंदकिशोर अग्रवाल
श्री मुकेश अग्रवाल, श्री गिरिराज गुप्ता, श्री हरि मंगल, श्री पुरूषोत्तम जिन्दल

नगर निगमों में घोर भ्रष्टाचार का तांडव-

जालसाजी पूर्ण रिकार्ड, नहीं दी छायाप्रतियां

डॉ. ए.के. पुराणिक, डॉ. गर्ग, सारडा, गौतम का नियुक्ति पत्र अंकसूची, गजट प्रकाशन नहीं दिया सारी अवैध नियुक्तियां

इंदौर। नगर निगम को 25 अगस्त 08 को सूचना के अधिकार में श्री अजमेरा ने एक आवेदन दिया था जिसका जवाब 23/9/08 को दिया गया, ताकि बिना पूछताछ किए सीधे पैसे जमा करवा कर उल्टी-सीधा रिकार्ड देकर आवेदक को भ्रमित कर समय पूरा कर दिया जाए। इन मक्कार शूकरों की फौज ने भी वही किया।

नगर निगम इंदौर स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों, लोक विश्लेषक, खाद्य निरीक्षकों, लाइसेंसिंग प्राधिकारी की योग्यता, गजट प्रकाशन, नियुक्ति पत्र मांगा गया था, जिनकी नियुक्ति उचित तरीके व योग्यता के साथ की गई थी। वह तो दे दिया गया, परंतु स्वास्थ्य अधिकारियों, लोक विश्लेषक की योग्यता के लिए अंक सूची, गजट प्रकाशन व नियुक्ति पत्र के कहीं अते-पते नहीं थे। यही नहीं इन हरामखोरों ने आवेदक से 10-12 चक्कर कटवाने के बाद ही दी जा रही सूचनाओं को सत्यापित और मुद्रांकित करके दिया।

वर्तमान में डॉ. ए.के. पुराणिक, डॉ. गर्ग, डॉ. नटवर सारडा के लंबे समय से पदस्थ होने के बाद भी जालसाजों ने एस.सी. गर्ग व डॉ. नटवर सारडा का ही नाम दिया और लिख दिया एम.बी.एस. हैं। न गजट प्रकाशन न नियुक्ति पत्र, न एम.बी.बी.एस. की अंक सूचियों का भी पता नहीं है। अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ने जिस धेमन का नाम दिया है, वह राजस्व विभाग के अंतर्गत होने के बाद भी उस खाद्य विभाग की अनुज्ञप्ति का कार्य लिया जा रहा है, जबकि न उसकी योग्यता है न उसके लिए पात्र, न ही उसे नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसके बाद भी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का कार्य देख रहा है। लोक विश्लेषक का कोई नाम ही नहीं है तो योग्यता, नियुक्ति पत्र, गजट प्रकाशन का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

पृष्ठ क्रमांक 52 पर 06/06/07 पत्र क्रमांक 13 में डॉ. एम.के. गौतम का हवाला दिया है, जिसके अंतर्गत एक रईस खान का नाम है जो मीट निरीक्षक के पद पर है। मीट निरीक्षक के नाम पर यह पूर्णतः अवैध नियुक्ति है, मीट निरीक्षक नाम का कोई पद शासन में नहीं है, न ही इसका कोई विवरण है। वे.... डॉ. ही इस कार्य को करते हैं। स्पष्टतः यह व्यक्ति जालसाजी पूर्ण तरीके से निगम से वेतन ले रहा है। इसकी भी योग्यता, नियुक्ति पत्र, गजट... इसलिए कोई जानकारी नहीं दी गई है।

बिन्दू क्रमांक 3 में भारी जालसाजी की गई है। 1.04.06 से 31.03.07 तक कितने नमूने लिए गए कुछ भी नहीं दिया गया है। जबकि 6 निरीक्षकों के हिसाब से 10 प्रतिशत खाद्यनिरीक्षक के हिसाब से 60 नमूने प्रति माह और वर्षभर से 720 नमूने लेने का भारतीय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि. 1954 में प्रावधान है (प्रति निरीक्षक 10 नमूने) जिसका खुला उल्लंघन है। 01.04.07 से 31.03.08 तक मात्र 414 नमूने लिए गए, जिसमें से मात्र 40 फेल हुए, कितने प्रकरण लगाए, कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोगशाला भी नगर निगम की जहां नेतागिरी ज्यादा काम बिलकुल नहीं होता है। जिनसे लेनदेन नहीं होता, बस वही नमूने फेल होते हैं, क्योंकि हर दुकानदार किसी न किसी नेता की दुकानदारी का चंदे वाला ग्राहक हैं। जो ग्राहक नहीं है उसका सब कुछ फेल, जो ग्राहक है उसका दुकानदार का सब कुछ फेल होने पर भी सब कुछ पास हो जाता है।

बिन्दु क्रमांक 04 व 05 में मोबाइल न्यायालय के मजिस्ट्रेट के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है कि मौके पर माल जब्त कर उसकी जांच कैसे की जाती है। क्या मोबाइल मजिस्ट्रेट स्वयं लोक विश्लेषक भी हैं। जो देखते ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जानकर नष्ट करने का आदेश देते हैं और चालान बनाकर दंड वसूलते हैं। प्राप्त किए गए 154 पृष्ठों में मुख्य पृष्ठ की कॉपी यहां प्रकाशित की जा रही है-

प्रति, दिनांक 19-9-2008
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिका निगम इंदौर
विषयः- सूचना के अधिकार के तहत चाही गई जानकारी बाबद् (ए.एस.पी. कुमार का पत्र) दिनांक 25-8-08।
संदर्भः- पत्र क्रं. 799 दिनांक 27-8-2008 तथा स्वास्थ्य विभाग का आवक क्रं. 2553 दिनांक 27-8-08 बाबद।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में चाही गई जानकारी इस प्रकार है-

(1) नगर निगम इंदौर में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी श्री डॉ. डी.सी. गर्ग है तथा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नटवर सारड़ा है तथा नगर निगम इंदौर में 5 खाद्य निरीक्षक कार्यरत हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं (1) गौतम भाटिया, (2) संदीप पाटोदी (3) लखन शास्त्री (4) राजेश जायसवाल (5) विवेक गंगराडे। नगर निगम की खाद्य प्रयोगशाला है तथा यहां श्री प्रदीप तिवारी जन विश्लेषक के पद पर कार्यरत है। खाद्य निरीक्षक के संबंध में नियुक्ति, क्षेत्राधिकार के संबंध में नोटिफिकेशन तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता की फोटो प्रति संलग्न है। खाद्य निरीक्षक वेतन श्रेणी 4500-7000 पर कार्यरत है।

(2) वर्तमान में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का कार्य श्री धेमन देखरहे हैं जो राजस्व विभाग के अंतर्गत हैं।

(3) वर्तमान में निगम में कार्यरत मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी तथा स्वास्थ्य अधिकारी एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण है तथा स्वास्थ्य संबंधित कार्य के भार साधक हैं। खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य अपमिश्रिण निवारण अधिनियम के तहत पत्र में दर्शाई गई अवधि में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने की संख्या इस प्रकार है-

दिनांक 1.4.06 से 31.3.07 तक	नमूनों की संख्या	नियमानुसार नहीं पाए गए नमूने
1.4.07 से 31.12.07 तक	294	31
1.1.08 से 31.3.08	120	29
1.1.08 से 31.3.08 तक	77	6
1.4.08 से 31.8.08 तक	79	14

(4) खाद्य निरीक्षक द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेने का कार्य किया जाता है। लोक विश्लेषक से अपमिश्रित नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने उपरान्त प्रकरण में अन्वेंषण कार्य करने पश्चात प्राधिकारी की स्वीकृति से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रकरण उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन इंदौर को प्रेषित किया जाता है। अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय में प्रकरण दायर करने के पश्चात स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा अपमिश्रित प्रकरणों में आरोपियों को सूचना पत्र निर्वाहित किया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक अपमिश्रित प्रकरणों में संबंधित खाद्य निरीक्षक न्यायालय में आरोप पूर्वतथा आरोप पश्चात साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित रहते हैं शासन द्वारा न्यायालय में इस हेतु स्पेशल मुनीसिपल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है साथ ही पूर्व से चल रहे प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित है। इसके साथ ही ऐसे आरोपियों जिन्हें निचली अदालतों में सजा सुनाई गई है, इन केसों में अपिली न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में भी प्रकरण प्रचलित है। समय-समय पर अपमिश्रित मामलों में नियमानुसार खाद्य निरीक्षकों द्वारा जप्त माल को माननीय न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत करना होता है।

(5) सभी खाद्य निरीक्षकों द्वारा उपरोक्त कार्य के साथ राज्य शासन द्वारा नियुक्त मोबाइल मजिस्ट्रेट के साथ खाद्य पेय उपविधि तथा नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत सप्ताह में 2 दिवस कार्य हेतु शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर त्रुटियां पाए जाने पर मौके पर ही चालानी कार्यवाही की जाती है, जिनमें मोबाइल मजिस्ट्रेट द्वारा मौके पर ही अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

(6) न्यायालयीन प्रकरणों में प्रत्येक खाद्य निरीक्षक को अनिवार्यतः सप्ताह में एक दिन तथा समय-समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर उनसे संबंधित प्रकरणों के दस्तावेज व आरोप पूर्व व आरोप पश्चात साक्ष्य हेतु उपस्थित होना पड़ता है।

(7) नगर पालिका अधिनियम 1956 के तहत विभिन्न उपविधियां तथा खाद्य एवं पेय पदार्थ उपविधियों के तहत सभी खाद्य निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से चालान बनाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना तथा सड़े-गले, खुले में विक्रयार्थ दूषित खाद्य पदार्थों के विनष्टिकरण की कार्यवाही की जाती है।

खाद्य निरीक्षकों द्वारा विगत 2 वर्षों में मोबाइल मजिस्ट्रेट के साथ तथा पृथक से लगभग 500 से अधिक चालान बनाए गए जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

(8) पर्यावरण की संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पोलीथीन केरीबेग्स के नमूने तथा पृथक करण की कार्यवाही कलेक्टर कार्यालय के गठित दल के अंतर्गत एसडीएम के निर्देशन में की गई है।

(9) प्रशासनिक आदेशों के तहत खाद्य निरीक्षकों को सौंपे गए अन्य कार्य जैसे असिस्टटेन्ट रेवेन्यू आफिसर पद का कार्य, अनंत चतुर्दशी जुलूस, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु खुले एवं दूषित खाद्य पदार्थों का विनष्टिकरण, क्लोरिन गोलियों का वितरण, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों को वितरित किए जाने वाले मध्यान्ह भोजन की जांच का कार्य, अतिविशिष्ट व्यक्तियों के शहर आगमन पर उनकोप्रस्तुत खाद्य पदार्थों की सघन जांच व गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उपसंचालक द्वारा लगाई गई ड्यूटी का निर्वाहन करने का कार्य किया गया है।

(10) पत्र में उल्लेखित विगत 2 वर्षों की अवधि में वर्ष 2006 से अधिकतम समय भारत सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार निर्वाचम नामावली के पुनरीक्षण के कार्य के तहत घर-घर जाकर निर्वाचन नामावली की सघन जांच, फोटो निर्वाचक नामावली में फोटो एवं फोटो परिचय पत्र तैयार करवाने हेतु मतदाता के फोटो एकत्रित करने का कार्य तथा फोटो परिचय पत्र वितरण करने का कार्य तथा अन्य दिए गए निर्देशों का सतत परिपालन किया जा रहा है। जिनके आदेशों की फोटोप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्न- 139 पृष्ठ
समस्त खाद्य निरीक्षक
नगर पालिका निगम, इंदौर
(1) गौतम भाटिया
(2) संदीप पाटोदी
(3) लखन शास्त्री
(4) राजेश जायसवाल
(5) विवेक गंगराडे

भारतीय...

पेज 8 से जारी

आम आदमी के नाम पर वित्तमंत्री पब्लिक चीट अम्बरम और धूर्त मनमोहन केवल घडियाली आंसू बहा रहे थे।

अब जब शेयर मार्केट के कृत्रिम और जालसाजी पूर्ण तरीके से भरी हवा निकलने लगी तो इन्हें अपने मक होते कमीशन की याद आने लगी। बैठते शेयर मार्केट में कुछ दो-चार दलालों ने आत्म हत्या क्या की कि भगदड़ मच गई। जब बढती महंगाईसे परेशान होकर मेहनत मजदूरी करने वाले दो करोड़ से ज्यादा लोग भूखे सो रहे थे, 8 करोड़ को दो वक्त का भोजन नसीब नहीं हो रहा था, तब इन हरामखोरों जो सत्ता में बैठे थे, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे थे, तो उन्हें इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गिरते सेन्सेक्स क रोकने के लिए जरूर इनह रामखोरों के दिलों की धड़कन तेज होने लगी और इन्होंने उन शेयर मार्केट के जुआरियों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में गरीबी रेखा से ऊपर, निम्न मध्यमवर्गीय से लेकर उच्च मध्यमवर्गीयों, नौकरीपेशा लोगों के जमा धन से बैंकों का धन उन जुआरियों, परस्पर निधि प्रबंध को बांटा जा रहा है, जिन्होंने अरबों रुपए के लाभ क तो स्वयं हजम कर लिया और घाटा खाने पर म्युचल फंड के निवेशकों के खाते में डाल कर उनकी जमा पूंजी चट करने में लगे हैं।

म्युचल फंड मिलकर डकारो फंड : म्युचल फंड के नाम पर अमेरिका को मेरिलालिंच जिसने भारत में डीएसपी मेरिल लिंच के नाम से अरबों रुपए का संग्रहण किया था इसी प्रकार राष्ट्र में चल रहे लगभग सैकड़ों से ज्यादा म्चुयल फंड सबकी कहानी एक जैसी ही है। इसमें जनता की छोटी-छोटी जमाओं को लेकर शेयर मार्केट में पैसा निवेशित किया जाता है। इसका सारा खेल म्युचल फंड के प्रबंधकों के हाथ रहता है। प्रबंधक उसके शेयर दलालों, पूंजीपतियों की रखैल के रूप में अपनी मोटी कमाई के लिए उस फंड के साथ मनमाने तरीके से निवेशित करते हैं। भारत की अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों के म्युचल फंडों की पूर्णतः यहीकहानी है। जहां तक रिलायंस, टाटा, बिरला, कोडक, महिन्द्रा जैसी 25 से ज्यादा कंपनियों के म्चुयल फंडों के बारे में बात करना ही मुर्खता होगी। यहांसारा सौदा उद्योगपतियों की मर्जी पर कार्य करता है। वहां सारे म्युचल फंड प्रबंधक अपनी मोटी कमाई का ध्यान रखते हुए उद्योगपतियों के इशारे पर नाचते चलते हैं। विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के फंडस जैसे मोरगन स्टेनली डी.एस.पी. मेरिल लिंच जैसी 50 से ज्यादा कंपनियों की बत्तमीजियां और भी उच्चस्तर की रही। उन जालसाजों ने तो भारत की जनता के धन का भी उपयोग किया और लाभ कमाया तो स्थानांतरण कर दिया।

भारत में मात्र यूटीआई देश का सबसे पहला म्युचल फंड भर ऐसा था, जिसने सन 1985 तक भर अच्छा कामकर निवेशकों को 80 प्रतिशत ईमानदारी से लाभांश दिया। इस पर उस वक्त तक म्युचल फंड मिलकर डकारो फंड की छाया नहीं पड़ी थी, परंतु जैसेही बाद की सरकारों की इस पर निगाह पड़ी, उन्होंने वहां राजनैतिक नियुक्तियां शुरूकर दी। बाद में 1988 में फेरवानी की नियुक्ति के बाद से नाम के अनुकूल भारी फेर और फरेब हुए। उसने अपनी कमाई के लिए दलाल हर्षद मेहता के इशारे पर रुपए 20000 करोड़ से ज्यादा का गच्चा दिया, बाकी 1994 तक अधिकांश म्युचल फंड राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ ही कुछ बड़े उद्योगों के थे, परंतु स्थिति 50 प्रतिशत से ज्यादा मिलकर डकारो फंड की ही थी।

यह सारा इतिहास प्रस्तुति के पीछे उद्देश्य यह था कि वि.मं. पब्लिक चीट अंबरम प्र.मं. मनमोहन और रिजर्व बैंक ने जोर रुपए 65000/- करोड़ रुपए जो कि जनता की जमा पूंजी जमाओं के रूप में बचत बैंक सावाधि आवर्ती खातों में चालू खातों में जमा धन के रूप में बैकों में है का उपयोग इन जुआरियों को जुआ खेलने के लिए 40% पर उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि सीधी सपाट भाषा में अवं भारतीय बैंकों का जमा धन इस प्रकार इन जुआरियों को बांटकर बैंकों को भी डुबोया जाए। उस बंदर बांट में पब्लिक चीटर वित्तमंत्री अरबों रुपए स्वयं भी डूबते बैंकों से अपने ास मिलने वालों के माध्यम से डकार लेगा। पहले बाजार को 23000 तक पहुंचाने में खाया। अब बचाने के बहाने बैंकों से ऋण के सस्ती दरों पर दिलवाकर खाएंगे।

अब प्रश्न यह उठता है कि जब बाजार 12 वर्षों की यात्रा करता हुआ 4000 से 23000 पहुंचा और जो लाभ कमाया वह कहां गया? अर्थात् लाभ का मीठा-मीठा गप करते गए अब गिरने से हानि हो रही है तो धूर्तों, जालसाजों का टोला चिल्ला रहा है। रिजर्व बैंक के नगदी आरक्षण अनुपात (सीआरआर) एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुपात), न्यूनतम ऋण दर, घटाने से सचमुच क्या बाजार बढा है। यह एकदम सफेद झूठ है। कुल मिलाकर अधिकांश देशों के वित्तमंत्री के इशारे पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और भारत से लेकर जापान जैसे छोटे से देशों ने भी अमेरिकी जालसाजियों के शिकार बैंकों के दीवालियापन आए स्टाक मार्केट की जुआरियों की मंदी के भूचाल को रोकने के लिए जिस तरह बैंकों के दरवाजे खोलकर अमेरिकी तरीके से जो बचाव के तरीके अपनाकर आम नागरिकों की जमाओं को आँख मींच कर बहाने की तैयारी शुरू की गई है। इस तरह से बैंकों को दीवालिया बनाने के साथ ही शासन तंत्र को खोखला बना दिया जाएगा।

साप्ताहिक
समय माया

कन्या भ्रूण हत्या, स्त्रियों की घटती संख्या भी कारण है-

समलैंगिकता आधुनिकता नहीं, अभिशाप

वर्तमान में विश्व में चारों तरफ समलैंगिकता को कानूनी मान्यता दिलाने का चलन अमेरिका से चलकर विश्व में फैलता हुआ भारत आ पहुंचा है। भारत में भी समलैंगिकता को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए समलैंगिक जोड़ों और समूहों ने सभी महानगरों में मुहिम चला रखी है, जो प्राकृतिक वंशवाद के चक्र के लिए वास्तविकता में तो अभिशाप है जो न केवल वर्तमान तो बिगाड़ ही रही है, भविष्य को पूर्णतः बाधित वरन नष्ट ही कर देगी। स्त्री व पुरुषों को न केवल अल्पायु, नीरस, वरन धरती की यात्रा को उनके जीवन काल तक समेट देगी। ऐसे सभी समलैंगिक जोड़ों की उनके अस्तित्व को, पृथ्वी पर आने के औचित्य को नकारते हुए भविष्य को समाप्त करते हुए अंतिम सिद्ध होगी।

बेशक उपरोक्त दलीलों, सत्यताओं को तत्काल आंकलन न तो किया ही जाएगा, न समय आएगा पर जीवन में वृद्धावस्था में फिर यह आंकलन किया भी गया तो औचित्यहीन बेमानी और यौवन काल की भूल पर पछताने के लिए भी शब्द नहीं छोड़ेगा।

पृथ्वी पर सत्यता में तो हर प्राणी जो नर व मादा होते हैं, समलिंगियों के साथ रहने पर ज्यादा सहज और सुरक्षित अनुभव करते हैं। यह बात केवल मानवों में ही नहीं वरन सभी स्तनपायी प्राणियों में पाई जाती है, पर इसके विपरीत यौनाचार में प्रकृति के वंशवाद के पीढ़ी और संतति पैदा कर सिद्धांत को चलाया जा सकता है। यही कारण है कि प्रकृति ने नर-नारी के जोड़े को ही सम्पूर्ण माना है। ताकि वे अपने ऋतुकाल में संभोग कर संतति पैदा कर प्रकृति के चक्र को चलायमान रख सकें।

इसके विपरीत मानवों में समलैंगिकता का बढ़ता रुझान नया तो नहीं और अप्राकृतिक भी नहीं कहा जा सकता, पर यौनाचार के मामले में तो इसे भारतीय आयुर्वेद ने भी आप्राकृतिक ही माना है।

वर्तमान में बढ़ती समलैंगिक प्रकृति, शादी का पंजीयन कराने वालों, कानूनी मान्यता की लड़ाई लड़ने वाले बताएं कि आज अगर शादी करके साथ रह भी लेंगे तो बिना बच्चों की कैसी गृहस्थी, कैसा घर, बच्चे नहीं तो पीढ़ी नहीं, आगे जीने और बच्चों और बच्चों के साथ जीने का सुख नहीं, क्यों समलैंगिक जोड़े कैसे और क्यों लंबे जीवन की कामना करेंगे?

समलैंगिकता में स्त्रीयों के रजस्त्राव

बंद होने के बाद और पुरुषों में वृद्धावस्था में योनांगों की शिथिलता के बाद जीवन समाप्त और स्वयं ही मृत्यु की कामना करने लगेंगे जो कि सफल दांपत्य जीवन में साधारण स्तर पर भी स्त्री पुरुष कभी नहीं करते।

साथ ही प्रकृति जन्य जो एक स्त्री को पुरुष के साथ रहने का सुख, सुरक्षा प्राप्त होती है, एक स्त्री को स्त्री के साथ रहने से वो तो नहीं मिल सकती, वही हाल पुरुषों का भी है जो स्त्री के साथ रहने में उसका जीवन पर्यन्त आकर्षण में बंधे रहकर जीवन जी पाता है, अधिकतम 10-20 वर्ष ही वह आकर्षण मन मार के बना सकता है।

इस पुरुषों की समलैंगिकता में एक कारण जो अदृश्य रूप से कार्य कर रहा है, कि स्त्रियों की कम होती संख्या, भविष्य बनाने ज्यादा धन कमाने के चक्कर में आदमियों/ पुरुषों को घर से बाहर रहकर किराये के मकानों में अपना/उनका सहयोगीबन कर रहना पड़ता है। यौनाचार के वेग में समलैगिंक संबंध बन जाते हैं। स्त्रियों के अभाव में स्त्रियों की बढ़ती आकांक्षाओं ने भी पुरुषों में समलैंगिकता की तरफ धकेला है। पर यह सब हुआ मजबूरियों में।

वर्तमान समय में स्त्रियों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं, बहु विधि अनेकों पुरुषों से संबंध रखने की प्रवृत्ति और बेवफाई से भी पुरुष हताश होकर समलैंगियों की तरफ आकर्षित हुए। निसंदेह समलैंगिकता की ये हवा दीर्घगामी नहीं होगी, चाहे स्त्रियों में हो या पुरुषों में, न ही ऐसे विवाह दीर्घगामी हो सकते हैं।

भारतीय न्यायालयों को स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को किसी भी हाल में इन्हें न तो कानूनी मान्यता देनी चाहिए, बेशक समय के ए इस तूफान की गति को मंद होने में समय लगेगा। बस इस संबंध में भारत शासन को इतना इन समलैंगिक संबंधों की पैरवी करने वालों को आश्वासन दे देना चाहिए कि उनके ऐसे संबंधों को व्यक्तिगत तौर पर कानूनी उलझनों में नहीं उलझाया जाएगा।

समलैंगिकता की बढ़ती प्रवृत्ति का एक मुख्य कारण यह भी है कि यौवनावस्था की अवस्था में 20 से 25 वर्ष की आयु में विवाह न हो पाना, दीर्घसमय तक अकेले रहने से बेहतर अपने समलैंगिक साथरह रहे, सहयोगियों से यौनाचार कर आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर लेना, फिर स्त्रियों की घटती संख्या भी इसके लिए जिम्मेदार है। जो स्त्रियां पढ़-लिख कर अपने दम पर जीवन यापन करती है वह स्वच्छंदता उन्हें पुरुष के बंधन में बंधने से रोकती है। इसलिए भी स्त्रियां समलैंगिकता की तरफ आकर्षित हो जाती है।

छात्रावासों में रहने वाले स्त्री-पुरुषों में उनके साथी ही उन्हें समलैंगिक यौना चार का आदी हो जाने पर उन्हें वहीं ज्यदा अच्छा लगने लगता है। इसी कारण ये हवा महानगरों में ज्यादा तेजी से बह रही है। वनं पर ही इसके लिए ज्यादा आंदोलन किए जा रहे हैं जो न केवल ऐसे स्त्री-पुरुषों के लिए दीर्घगामी, स्वयं के लिए अभिषाप सिद्ध होंगे, वरन समाज के राष्ट्र के व विश्व के लिए भी अभिषाप सिद्ध होंगे।

एड्स-डे, कंडोम-डे-स्वच्छंद यौनाचार दिवस

एड्स के नाम, कंडोम की बिक्री

कंडोम की आदत डाल देश को थाईलैंड बनाने का षडयंत्र

पूरे विश्व में 2 दिसम्बर को एड्स-डे मनाया गया। 20 वर्ष पूर्व छोड़े गए एड्स के शिगूफे से, वर्तमान में प्रतिदिन पूरे विश्व में अरबों कंडोम बिकते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 2 से 5 करोड़ कंडोम प्रतिदिन भारत में ही बिक जाते हैं। 10 पै. का रबर का ये फुग्गा रुपए 3 से 10 प्रति नग में बिकता है।

एड्स नाम की दुनिया में कहीं कोई बीमारी नहीं है। जिन्हें एड्स का रोगी बताया व बनाया जाता है उनके संबंध में जब डॉक्टर किसी भी बीमार को आंतरिक कमजोरियों और कई बीमारियों के चलते यह पता लगाने में और इलाज करने में असफल हो जाते हैं उसे कंडोम का नाम देकर मुक्ति पा ली जाती है। डॉक्टर, नर्सें, उसको छूने से मना कर देते हैं।

एड्स का भय फैलाकर वर्तमान में अरबों रुपए प्रति दिन की कमाई की जा रही है। सीधा सा गणित यह है कि 10 पैसे के कंडोम पर 25 पै. बाजार व्यवस्था के अंतर्गत भय फैलाने, 25 पैसे डॉक्टरों को खिलाने पर भी खर्च किया गया तो भी 200 से 2000/- का मुनाफा तो इनको मिल ही रहा है। फिर जब तक लोगों को आदत नहीं लगी थी तब तक ही सारा खर्च था। अब तो कालेज की लड़कियों से लेकर घरेलू महिलाएं भी जो कई पुरुषों से, संबंध रखती है, साथ लेकर ही चलती है ताकि मजे में गर्भ ठहरने की सजा न भुगतनी पड़े, युवा पीढ़ी भी अब किसी के साथ भी संबंध बनाने से नहीं हिचकती, न ही चूकती है क्योंकि इसलिए पुरुष भी कंडोम साथ में रखने लगे हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के कंडोम की बिक्री बढ़ाने के लिए विदेशों से अरबों रु. हर वर्ष एड्स का भय फैलाकर, जान-बूझकर कुछ बीमारियों को लाइलाज या अनेकों बीमारियों से पीड़ित हो

जाते हैं, एड्स की घोषणा करदी जाती है। ताकि मीडिया इस खबर को उछाले, जनता भयभीत हो, कंडोम का प्रयोग करने के लिए प्रेरित हो, भारत के माध्यमिक स्कूली शिक्षा में भी महाभ्रष्ट, नीच मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह यौन शिक्षा देने के पीछे भी मूल कारण यही है, कि किशोरावस्था में ही यौनाचार की तरफ आकर्षित कर यदि यौनाचार में उलझा दिया जाये, उसी समय कंडोम के प्रयोग की आदत डाली जायेगी, तो न केवल मुक्त यौनाचार को बढ़ावा मिलेगा, वरन कंडोम की तह युवा पीढ़ी जिंदगीभर ग्राहक बनी रहेगी। इसके साथ भारत की प्रतिभाओं ने जो विश्व में अपना झंडा गाड रखा है, उस युवा पीढ़ी को किशोरावस्था में ही यौनाचार में उलझाकर वहीं बर्बाद किया जा सकेगा, स्वच्छंद यौनाचार में उलझी रहेगी युवा पीढ़ी ज्यादा न तो पढ़ लिख पायेगी, न ज्यादा दिमाग खर्च करने लायक रहेगी, तो फिर शासन में बैठे सत्ताधीश क्या भ्रषअटाचार और लूटपाट कर रहे हैं। आतंकवाद फैला रहे हैं, देश बेच रहे हैं। किसी पर भी उनका ध्यान नहीं जायेगा।

केंद्र शासन में बैठा स्वास्थ्य मंत्री ए रामदास और मा.सं. मंत्री अर्जुन सिंह की नीचता, षडयंत्रकारी प्रवृत्तियों के चलते इन्होंने पिछले चार वर्षों में क्या गुल खिलाये हैं, ये देश जानता है। इन श्वानों को रह-रहकर स्कूली शिक्षा में यौनाचार पढ़ाने का जो शौक चर्राता है उसके पीछे कंडोम कंपनियों का धन लागू करवाने का फंडा ही होता है।

इस एड्स दिवस मनाने बनाम कंडोम दिवस मनाने का स्कूलों में प्रभातफेरियां निकालना, चौराहों पर षडयंत्रपूर्वक प्रचार करना, म.प्र. शासन में तो पूरी एड्स कंट्रोल सोसायटी जिसका कार्यालय म.प्र. तिलहन संघ के भवन में चल रहा है जहां बड़े-बड़े अधिकारियों की खूबसूरत बीवीयां, बेटियां बैठाई गई है, जो न केवल इस षडयंत्रकारी काम को वर्षों से करती आ रही है, स्वच्छंद यौनाचार में लिप्त रहकर स्वच्छंद यौनाचार की प्रेरणा युवा पीढ़ी व युवा होती पीढ़ी को माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों में दे रही हैं।

एड्स की बीमारी से पिछले 30 वर्षों में कहीं, कोई नहीं मरा, इसके विपरीत इसके लिए पूरा एक विभाग चल रहा है, तो केवल कंडोम बेचने के लिए, जबकि मलेरिया ही इस देश में 20 लाख मौते, क्षय रोग से 40 लाख मौते, हर वर्ष नियमित रूप से पिछले 30 वर्षों से हो रही है। दो वर्ष पूर्व अकेले चिकनगुनिया से केरल, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, बिहार, म.प्र., महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा में ही लगभग 1 करोड़ लोगों की मौतें हो गई थी, पर शासन के हरामखोरों ने उसका कोई स्थायी इलाज नहीं निकाला। **शेष पेज 2 पर**

वि.मं. पब्लिक चीट अंबरम का जुआरियों को तोहफा

भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों को दीवालिया बनाने का षड्यंत्र

रिजर्व बैंक रुपए 65000 करोड़ शेयर मार्केट सेंसेक्स को उठाने के लिए लुटाएगा

भारतीय शेयर बाजार जो कि विशुद्ध जुआरियों का अड्डा है और रिलायंस, टाटा जैसे खिलाड़ियों, उद्योगपतियों की कठपुतली है। विश्व के शेयर बाजारों की चपेट, विदेशी निवेशकों और भारतीय निवेशकों, पारस्परिक निधि, म्यूचल फंडों की बिकवाली दबाव से टूटकर 110,000 से नीचे चला गया था। जो कि जाना ही था, आखिर कृत्रिम रूप से जुआरियों, पूंजीपतियों के दम पर उसे कब तक फुलाए रखा जा सकता था। फिर विदेशी निवेशकों, पारस्परिक निधि प्रबंधक, धन कमाने आए थे। 1995 से उन्होंने अपना धन जब सूचकांक 4 हजार था तब से उसमें निवेश करना शुरू किया था, आज नहीं तो कल उन्होंने लाभ निकालकर बिकवाली तो करना ही थी, उन्होंने की और धर्नाजन किया, फिर उ्हें भी तरलता चाहिए ती इसलिए भी हमारे स्टाक बिकवाल ही क़े अतिरिक्त उनके पास कोई चारा भी नहीं था।

शेयर मार्केट की इस उठापटक में रिजर्व बैंक और स्वयं शासन को ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि जब जुआरी निवेशक धन कमा रहे थे तब तो दोनों हाथोंसे बटोरते समय न तो देश की महंगाई पर ध्यान था, न गरीब आदमी की भूख पर, जबकि बढ़ती महंगाई से लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को दो वक्त की रोटी भी छीनी जा रही थी तब सत्ता में बैठे धूर्तों के पास भी कमीशन बटोरने के अतिरिक्त केवल **शेष पेज 7 पर**

प्रतिबंधात्मक सूचना

इस समाचार पत्र एवं वेबसाइट में प्रकाशित समाचार सामग्री का पूर्ण-अपूर्ण या उसके आधार पर बनाये गये अन्य समाचार, टीवी समाचारों, टीवी एपिसोड, इंटरनेट साइटों पर नगर, प्रदेश व राष्ट्र या राष्ट्र के बाहर विश्व में किसी समाचार पत्र पत्रिका, टीवी समाचारों, डाक्यूमेंट्री या धारावाहिकों में बिना लिखित आदेश व अनुमति के उपयोग न करें. अन्यथा कॉपी राइट एक्ट के अंतर्गत इन्दौर न्यायालय में क्षतिपूर्ति एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र इंदौर रहेगा। इस समाचार पत्र की प्रतियां लेकर कुछ जालसाज ढोंगी पत्रकार होने का ढोंग कर पैसे, चंदा, सम्मेलनों के नाम पर धन वसूली करने की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसी किसी भी अवस्था में आप सीधे मोबाइल पर चर्चा कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं. अन्यथा सीधी पुलिस और कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं.

आज्ञा से
प्रधान संपादक

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु. 299-अंबेडकर नगर, इन्दौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इन्दौर द्वारा मुद्रित. बडवानी प्रतिनिधि-नरेश नायक मो. 94250-90602, भुपेन्द्र बिल्लोरे मो.99934-49774
कम्प्यूटराईजेशन- सुनील जोशी 93290-40982, भोपाल प्रतिनिधि एस.के. भारद्वाज मो.94256-37958, जबलपुर प्रतिनिधि श्री चंद्रकुमार जैन, इन्दौर कार्या. फोन 2309377 मो. 93007-55803